यूनेस्को प्रेस विज्ञप्ति सं. 2020-XX

यूनेस्को की रिपोर्ट से पता चलता है कि कोविड-19 संकट के दौरान सबसे गरीब देशों में से 40% देश शिक्षार्थियों की सहायता करने में विफल रहे और वह उनसे ऐसे शिक्षार्थियों को शिक्षा में शामिल करने का आग्रह करता है

पेरिस, 23 जून - यूनेस्को की *2020 वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट: समावेश और शिक्षा - सब यानी सभी* के अनुसार 10% से कम देशों में ऐसे कानून हैं जो शिक्षा में पूर्ण समावेश को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

यह रिपोर्ट पृष्ठभूमि, पहचान और क्षमता (अर्थात् लिंग, आयु, स्थान, गरीबी, दिव्यांनगता, जातीयता, देशीयता, भाषा, धर्म, प्रवास या विस्थापन स्थिति, यौन शिक्षा या लिंग पहचान अभिव्यक्ति, अंतर्विरोध, विश्वास और दृष्टिकोण) सहित दुनिया भर में शिक्षा प्रणालियों में शिक्षार्थियों का बहिष्कार किए जाने के महत्वपूर्ण कारणों का गहन विश्लेषण प्रदान करती है। यह बताती है कि कोविड-19 महामारी के दौरान बहिष्कार और अधिक बढ़ गया और ऐसा अनुमान है कि निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले लगभग 40% देशों ने अस्थायी स्कूल बंद होने के दौरान वंचित शिक्षार्थियों का समर्थन नहीं किया है।

2020 वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट (जीईएम) में देशों को स्कूलों के फिर से खुलने पर ऐसे लोगों पर अधिक ध्यान देने का आग्रह किया गया है जो पिछड़ गए हैं ताकि समाज को अधिक लचीला और समान बनाया जा सके।

यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले ने कहा, 'वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए, व्यापक समावेशी शिक्षा को अपनाना बेहद जरूरी है'। "कोविड-19 महामारी, जो अधिक विकराल रूप ले रही है और असमानता को बढ़ावा दे रही है, के बाद शिक्षा के भविष्य पर फिर से विचार करना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम इसमें असफल रहते हैं तो समाज की प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी।"

शिक्षा से वंचित रखा जानाः इस वर्ष की रिपोर्ट, सतत विकास एजेंडा 2030 के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए शिक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने में 209 देशों की प्रगति की निगरानी के लिए चौथी वार्षिक यूनेस्को जीईएम रिपोर्ट है। इसमें उल्लेख किया गया है कि 258 मिलियन बच्चों और युवाओं को शिक्षा से पूरी तरह से वंचित रखा गया था, और इसमें सबसे बड़ी समस्या गरीबी थी। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, सबसे गरीब परिवारों की तुलना में सभी परिवारों में सबसे अमीर 20% किशोरों में निम्न माध्यमिक स्कूल को पूरा करने की संभावना तीन गुना थी। निम्न माध्यमिक शिक्षा पूरी करने वालों में, सबसे गरीब परिवारों के लोगों की तुलना में सबसे अमीर परिवारों के छात्रों में बुनियादी

शिक्षा और गणित कौशल प्राप्त करने की संभावना दो गुणा थी। 2030 तक सार्वभौमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के घोषित लक्ष्य के बावजूद, कम से कम 20 देशों में शायद ही किसी गरीब ग्रामीण युवती ने माध्यमिक स्कूल शिक्षा पूरी की है, जिनमें से अधिकांश देश उप-सहारा अफ्रीका में हैं।

इसके अलावा, रिपोर्ट के अनुसार, मध्य और उच्च-आय वाले देशों में 10 साल के छात्र, जिन्हें अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा में पढ़ाया जाता है, ने आम तौर पर पढ़ने की परीक्षा लेने पर स्थानीय बच्चों की तुलना में 34% कम अंक प्राप्त किए। दस कम और मध्यम आय वाले देशों में, सामान्य बच्चों की तुलना में दिव्यांग बच्चों में पढ़ने में न्यूनतम प्रवीणता प्राप्त करने की संभावना 19% कम पाई गई। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, लगभग तीन गुणा एलजीबीटीआई छात्रों ने यह कहा कि वे स्कूल में असुरक्षित महसूस करने के कारण घर पर रहे थे।

असमानता का आधार: आज के प्रकाशन के साथ-साथ, यूनेस्को जीईएम रिपोर्ट टीम ने दुनिया में हर देश के लिए शिक्षा में समावेश से संबंधित कानूनों और नीतियों के बारे में जानकारी देने के लिए पीईईआर नामक एक नई वेबसाइट शुरू की। पीईईआर से पता चलता है कि कई देश अभी भी शिक्षा में भेदभाव बरतते हैं, जो रूढ़िवादिता, भेदभाव और अलगाव को बढ़ावा देता है। कुल देशों में से एक-चौथाई देशों के कानून में दिव्यांग बच्चों को अलग परिवेश में शिक्षित किया जाना अपेक्षित है, जबकि लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के साथ-साथ एशिया में यह 40% से अधिक है।

घोर बहिष्कार: अफ्रीका में दो देशों में अभी भी गर्भवती लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध है, 117 देशों में बाल विवाह होता है, जबकि 20 देशों द्वारा अभी तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के *कन्वेंशन 138* का समर्थन किया जाना है, जो बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। कई मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों में, रोमा बच्चों को मुख्यधारा के स्कूलों में अलग कर दिया गया था। एशिया में, रोहिंग्या जैसे विस्थापित लोगों को समानांतर शिक्षा प्रणालियों में पढ़ाया जाता था। ओईसीडी देशों में, आप्रवासी पृष्ठभूमि के दो-तिहाई से अधिक छात्रों ने ऐसे स्कूलों में भाग लिया, जहां बच्चों की संख्या कम से कम 50% थी, जिससे उनकी शैक्षिक सफलता की संभावना कम हो गई।

"कोविड-19 ने हमें अपनी शिक्षा प्रणालियों के बारे में नए सिरे से सोचने का सही अवसर दिया है," वैशिवक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट के निदेशक मानोस एंटोनिनिसस ने कहा, "मूल्यों और विविधता का स्वागत करने वाली दुनिया को रातों-रात पैदा नहीं किया जा सकता। एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को पढ़ाने और एक ऐसा माहौल बनाने, जहां छात्र सबसे बेहतर ढंग से सीखते हैं, के बीच बड़ा फासला है। लेकिन, कोविड-19 ने हमें दिखाया है कि यदि हम इस दिशा में सोचें तो हम चीजों को अलग तरह से कर सकते हैं।"

माता-पिता के भेदभावपूर्ण रवैए को समावेश में एक बड़ी समस्या माना गया: जर्मनी में लगभग 15% माता-पिता और हांगकांग, चीन में 59% को यह आशंका थी कि दिव्यांग बच्चे दूसरों के सीखने में बाधा डालते हैं। कमजोर बच्चों के माता-पिता भी उन्हें ऐसे स्कूलों में भेजना चाहते हैं जहां उनका ख्याल रखा जाए और उनकी जरूरतें पूरी हों। क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में, विशेष स्कूलों के 37% छात्रों ने मुख्यधारा वाले स्कूलों को छोड़ दिया था।

रिपोर्ट से पता चलता है कि शिक्षा प्रणाली प्राय: शिक्षार्थियों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखने में विफल रहती है। दुनिया भर में केवल 41 देशों ने सरकारी तौर पर सांकेतिक भाषा को मान्यता दी है और, विश्व स्तर पर मान्यता-प्राप्त स्कूल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की तुलना में इंटरनेट का उपयोग करने के लिए अधिक उत्सुक थे। लगभग 335 मिलियन लड़कियां ऐसे स्कूलों में गई जहां उन्हें पानी, स्वच्छता और स्वच्छता सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, जो उनके मासिक धर्म के दौरान कक्षा में भाग लेने के लिए आवश्यक थीं।

अलगाव महसूस करने वाले शिक्षार्थी: जब शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती, तो वे अलगाव महसूस कर सकते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में केवल 44% लड़कियों और महिलाओं, बांग्लादेश में 37% और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 24% को माध्यमिक स्कूल की अंग्रेजी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में इसकी जानकारी दी गई थी। 49 यूरोपीय देशों में से 23 के पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा, लैंगिक पहचान या अभिव्यक्ति के मुद्दों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है।

शिक्षकों को समावेशिता के बारे में प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है जो उप-सहारा अफ्रीका के दस फ्रैंकोफोन देशों में 10 प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों में से 1 शिक्षक ने कहा कि उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था। 48 देशों के एक-चौथाई शिक्षकों ने बताया कि उन्हों दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए और अधिक प्रशिक्षण की जरूरत थी।

पिछड़े बच्चों पर पर्याप्त आंकड़ों की अत्यधिक कमी। लगभग आधे निम्न और मध्यम आय वाले देश दिव्यांग बच्चों के बारे में पर्याप्त शिक्षा संबंधी आंकड़े नहीं रखते हैं। व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर शिक्षा संबंधी आंकड़े प्राप्त करने के लिए घरेलू सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। लेकिन दुनिया के 41% देशों - जहां दुनिया की 13% आबादी रहती है - में ऐसे सर्वेक्षण नहीं किए जाते या ऐसे सर्वेक्षण से आंकड़े नहीं जुटाए जाते। शिक्षा संबंधी आंकड़े अधिकतर स्कूल से लिए जाते हैं, जिसमें स्कूल न जाने वाले बच्चों का लेखा-जोखा नहीं होता।

एंटोनिस का कहना है कि "पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध न होने का अर्थ है कि हमें तस्वीर के काफी बड़े हिस्से की जानकारी नहीं है"। "इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कोविड-19 के दौरान अचानक सामने आई असमानताओं ने हमें चौंका दिया है।"

समावेशिता की दिशा में प्रगति के संकेत: रिपोर्ट और इसकी पीईआरई वेबसाइट में कहा गया है कि कई देश समावेशन को लागू करने के लिए सकारात्मक, नवीन दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे थे। कई देश स्कूलों में संसाधन केंद्र स्थापित कर रहे थे और प्रमुख प्रतिष्ठानों को दिव्यांग बच्चों को शामिल किए जाने में समर्थ बना रहे थे, जैसा कि मलावी, क्यूबा और यूक्रेन में हुआ था। गाम्बिया, न्यूज़ीलैंड और समोआ देश वंचित आबादी तक पहुंच बनाने के लिए घुमंतू शिक्षकों का इस्तेमाल कर रहे थे।

कई देशों को विभिन्न शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लीक से हटकर कदम उठाते हुए देखा गया था: उदाहरण के लिए, भारत के ओडिशा राज्य ने अपनी कक्षाओं में 21 आदिवासी भाषाओं का इस्तेमाल किया, केन्या ने खानाबदोश कैलेंडर के हिसाब से अपने पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाई और ऑस्ट्रेलिया में, शिक्षकों द्वारा 19% छात्रों के पाठ्यक्रम को समायोजित किया गया था ताकि उनके अपेक्षित परिणाम छात्रों की जरूरतों से मेल खा सकें।

रिपोर्ट में सब यानी सभी नामक डिजिटल अभियान की सामग्री शामिल की गई है, जिसमें अगले दस वर्षों की प्रमुख सिफारिशों के एक सेट का उल्लेख किया गया है।

****

बी-रोल, फोटो, साक्षात्कार, वीडियो और एनिमेशन तथा अधिक जानकारी के लिए केट रेडमैन k.redman@unesco.org +33(0)671786234 से संपर्क करें।

संपादकों के लिए टिप्पणियां

रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रेस किट पर जाएँ जिसमें रिपोर्ट और मल्टीमीडिया सामग्री है। (पासवर्ड: **AllmeansAll)**

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट (जीईएम रिपोर्ट) एक स्वतंत्र टीम द्वारा तैयार की गई है और इसे यूनेस्को द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह शिक्षा पर सतत विकास लक्ष्य, एसडीजी 4 को पूरा करने में प्रगति की निगरानी का एक आधिकारिक अधिदेश है।

पीईईआर वेबसाइट 23 जून से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी। तब तक, पत्रकार निम्नलिखित पासवर्ड का उपयोग करके साइट देख सकते हैं:

- https://www.education-profiles.org
- यूज़रनेम: team
- पासवर्ड: **gemprofiles246!**